विचार बिन्दु

बच्चों को पालना, उन्हें अच्छे व्यवहार की शिक्षा देना भी सेवाकार्य है, क्योंकि यह उनका जीवन सुखी बनाता है। –स्वामी रामसुखदास

लोकलुभावन नहीं 2047 के भारत की इबारत है नया बजट

संभवत: यह पहला अवसर होगा जब केन्द्रीय वित मंत्री द्वारा बजट पेश करते समय चुनावों में राजनीतिक लाभ हानि पर विचार किये बिना समग्र विकास और दीर्घकालीन आर्थिक सुधार को ध्यान में रखते हुए बजट प्रस्तुत किया है। कुछ माहों में ही पं. बंगाल, तमिलनाडू, केरल, असम और पुडुचेरी के चुनाव की तिथियां घोषित हो जाएगी। अब तक होता यह आया है कि बजट में चुनाव वाले राज्यों के नागरिकों को लुभाने के लिए खास घोषणाएं होती है। पर वित मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजनीतिक लाभ हानि के स्थान पर समग्र सुधारों और सरकार के मिशन 2047 को केन्द्र में रखकर 2027–28 का बजट पेश किया है। निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वां बजट पेश किया है। खासबात यह कि 2019 से 2026 तक लगातार नवां बजट पेश करने तक वित मत्री सीतारमण भिन्न भिन्न प्रदेशों की हथकरघा साड़ियों में नजर आई है। इस बार तमिलनाडू की बैंगनी कांजीवरम सिल्क साड़ी में नवां बजट पेश किया।

इस साल का बजट इसलिए भी मायने रखता है कि दुनिया के देशों के हालात और वैश्विक परिस्थितियां दिन प्रतिदिन विपरीत होती जा रही है। बजट के दिन जहां शेयर बाजार धराशाही हो गया वहीं दूसरे दिन ही अमेरिका द्वारा टैरिफ दर कम करने के साथ ही शेयर बाजार ने उंची उड़ान भर डाली। पर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए भारत की आर्थिक विकास की गति बनाए रखना किसी गंभीर चुनौती से कम नहीं है। विपरीत हालातों में भी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हमारी है। दुनिया के देश जहां आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था ने उंचाई प्राप्त की है। अमेरिका में ट्रंप 2 के बाद से दुनिया के हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं पर जिस रणनीति से भारत ने अमेरिका को इग्नोर की नीति पर चलते हुए चुनौती दी इसी का परिणाम है कि ट्रंप को टेरिफ दरें घटानी पड़ी है। हांलाकि ट्रंप के मिजाज को देखते हुए कुछ कहा नही जा सकता कि कब बह पलटी मार जाएं।

केन्द्रीय बजट की इसलिए सराहना की जानी चाहिए कि वैश्विक हालातों को देखते हुए दीर्घकालीन आर्थिक सुधार, देश में ढांचागत विकास और युवाओं, महिलाओं, किसानों सभी को साधने का जो समग्र प्रयास हुआ है उससे निश्चित रुप से आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को नई दिशा मिलेगी। विश्लेषक इसे समग्र सुधारों के साथ विकास का संकल्प बता रहे हैं तो कोई इस बजट को भारत की आत्मनिर्भरता का कवच बता रहे हैं। कोई इसे एमसएएमई सेक्टर का ग्रोथ इंजन बता रहे हैं तो कोई शी मार्ट के माध्यम से महिला सशक्तिकरण बता रहे हैं। वित मंत्री निर्मला सीतारमण इसे तीन कर्तव्यों उत्पादकता को बढ़ावा, आंकाक्षाओं को पूरा करना और सबका साथ सबका विकास पूरा करने का माध्यम बता रही है। इस बजट में प्राथमिकता लोकलुभावन को नहीं देकर देश को सशक्त आधार देने वाला बनाया गया है। एक और रक्षा बजट को बढ़ाया है। आज दुनिया के जिस तरह के तनाव के हालात बने हुए हैं और हमारे पड़ोसी बांग्लादेश के हालात है, उधर रुस यूक्रेन युद्ध थमने का ही नाम नहीं ले रहा है, ईरान अमेरिका के हालात कब युद्ध में बदल जाएं कहा नहीं जा सकता है और पाकिस्तान कब अपनी उद्दंडता दिखा दे कुछ कहा नहीं जा सकता, चीन के इरादे हमेशा संदिग्ध रहे हैं ऐसे में रक्षा क्षेत्र में बजटीय प्रावधान बढ़ाना और सैन्य क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाना समय की मांग है। इसी तरह से डिजिटल युग में दुनिया के देशों से दो कदम आगे बढ़ना समय की मांग है। एआई के युग को देखते हुए एआई को रोजगार का माध्यम बनाना, कौशल विकास, तकनीक से शिक्षा को जोड़ने, पर्यटन विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, यहां तक कि गाइड्स तैयार करने से लेकर चुवाओं और रोजगार से जुड़े सभी क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के प्रावधान किये गये हैं। खेती–किसानी को प्रोत्साहित करने के साथ ही जल के महत्व को समझा गया है। अमृत सरोवर से जल संग्रहण से लेकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।

कहने को लाख आलोचनाएं की जा सकती है पर वैश्विक हालातों को देखते हुए जिस तरह का भविष्योन्मुखी ठोस आधारभूत विकास का बजट होने से इससे दीर्घकालीन लाभ मिलेगा और अर्थव्यवस्था को बूस्ट प्राप्त होगा। सबसे खास बात यह है कि इस बजट के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि लोकलुभावन ही नहीं आमजन दीर्घकालीन आर्थिक विकास के बजट का आगे बढ़कर स्वागत करते है। अब बजटीय व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन का भी समयबद्ध रोडमैप बन जाए तो निश्चित रुप से इसका वास्तविक लाभ मिल सकेगा।

किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए बेहतर लोजिस्टिक प्रमुख आवश्यकता है। रक्षा के बाद सबसे अधिक प्रावधान बेहतर कनेक्टिविटि को दिया गया है। बेहतर आवागमन से विकास को गति मिलती है तो योजनाबद्ध शहरी विकास पर जोर दिया गया है। यदि सार रुप में कहा जाए तो यह बजट आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने का रोडमैप कहा जा सकता है। विनिर्माण क्षेत्र को गति, आधारभूत संरचना विकास, कौशल विवकास, एमएसएमई को प्रोत्साहन, उर्जा विकास व सहज उपलब्धता, इकोसिस्टम बनाए रखते हुए समग्र विकास पर जोर रहा है। हांलाकि नौकरी पेशा लोग आयकर में किसी तरह का परिवर्तन नहीं करने से निराश हुए हैं तो शेयर मार्केट में सट्टेबाजी को निरुत्साहित करने से निराशा हुई और इसका तत्काल असर शेयर बाजार पर देखा गया। कहने को लाख आलोचनाएं की जा सकती है पर वैश्विक हालातों को देखते हुए जिस तरह का भविष्योन्मुखी ठोस आधारभूत विकास का बजट होने से इससे दीर्घकालीन लाभ मिलेगा और अर्थव्यवस्था को बूस्ट प्राप्त होगा। सबसे खास बात यह है कि इस बजट के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि लोकलुभावन ही नहीं आमजन दीर्घकालीन आर्थिक विकास के बजट का आगे बढ़कर स्वागत करते है। अब बजटीय व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन का भी समयबद्ध रोडमैप बन जाए तो निश्चित रुप से इसका वास्तविक लाभ मिल सकेगा।

–अतिथि सम्पादक,
डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
(वरिष्ठ लेखक)

ट्रंप डील और मोदी नेतृत्व

राजस्थान के उद्योग के लिए नए अवसरों का द्वार

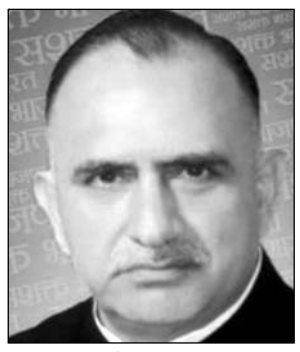

अशोक परनामी

भारत और अमेरिका के बीच लंबे इंतजार के बाद संपन्न हुई नई ट्रेड डील ने न केवल दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई दी है, बल्कि राजस्थान जैसे निर्यात–आधारित राज्यों के लिए यह समझौता उम्मीदों का नया क्षितिज खोलता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारतीय उत्पादों पर टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत करने का निर्णय ऐसे समय आया है, जब वैश्विक बाजार में अस्थिरता और संरक्षणवाद की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। इस पृष्ठभूमि में यह समझौता भारत की बढ़ती वैश्विक साख और प्रभावी आर्थिक कूटनीति का प्रमाण माना जा रहा है।

इस ऐतिहासिक समझौते के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बीते एक दशक में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद वैश्विक साझेदार के रूप में स्थापित किया है। 'मेक इन इंडिया', 'आत्मनिर्भर भारत' और 'वोकल फॉर लोकल' जैसे अभियानों को अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता दिलाने में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। अमेरिका जैसे प्रभावशाली देश द्वारा टैरिफ में इतनी बड़ी कटौती इस बात का संकेत है कि भारत अब शर्तें तय करने वाली अर्थव्यवस्था बन रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा इस डील को 'गेम चेंजर' करार देना भी इसी तथ्य को रेखांकित करता है कि केंद्र के मजबूत नेतृत्व का सीधा लाभ राज्यों तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले छह वर्षों में नौ महत्वपूर्ण ट्रेड डील कर यह साबित किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब आत्मविश्वास के साथ वैश्विक मंच पर खड़ी है। टैरिफ कटौती का सीधा और तात्कालिक असर राजस्थान के ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, गारमेंट और स्टोन उद्योगों पर दिखाई देने लगा है। उद्योग संगठनों के अनुसार, टैरिफ बढ़ने के बाद राज्य का निर्यात करीब 50 प्रतिशत तक गिर गया था। कई इकाइयां बंद होने की कगार पर थीं और हजारों कारीगरों व श्रमिकों की आजीविका पर संकट मंडरा रहा था। अब अमेरिकी बाजार से दोबारा पूछताछ और ऑर्डर मिलना शुरू होने से उद्योग जगत में नया उत्साह है।

जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में फैला जेम्स एंड ज्वैलरी उद्योग राजस्थान की वैश्विक पहचान का प्रतीक है। रंगीन पत्थरों और पारंपरिक राजस्थानी डिजाइनों की अंतरराष्ट्रीय मांग टैरिफ वृद्धि के कारण लगभग ठप हो गई थी। उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों का कहना है कि टैरिफ घटने के बाद अमेरिका सहित अन्य बाजारों से मांग लौटने लगी है। इससे कारीगरों और निर्यातकों को नई ऊर्जा मिली है।

अमेरिका जैसे बड़े खरीदार पर काफी हद तक निर्भर स्टोन इंडस्ट्री टैरिफ बढ़ने से सबसे अधिक प्रभावित हुई थी। 70 प्रतिशत से अधिक इकाइयों पर इसका नकारात्मक असर पड़ा। अब टैरिफ कटौती के बाद अमेरिकी खरीदारों की सक्रियता बढ़ने से उत्पादन और रोजगार दोनों में सुधार की उम्मीद है। इसी तरह तीन लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने वाला जयपुर का गारमेंट उद्योग एक बार फिर रफ्तार पकड़ने को तैयार है। निर्यात में गिरावट से जूझ रहे एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से राहतभरा साबित हो रहा है।

राजस्थान का हस्तशिल्प, ब्लू पॉटरी, लकड़ी का काम, संगमरमर की नक्काशी और हाथ से बने वस्त्र अमेरिकी बाजार में लोकप्रिय रहे हैं। टैरिफ घटने से जयपुर और जोधपुर के कारीगरों को बेहतर दाम और स्थिर बाजार मिलने की संभावना है। यह न केवल आर्थिक लाभ देगा, बल्कि सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी सहायक होगा। निर्यात में वृद्धि का असर केवल उद्योगों तक सीमित नहीं रहेगा। परिवहन, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग, बैंकिंग और बीमा जैसे सहायक क्षेत्रों में भी गतिविधियां बढ़ेंगी। यह 'मल्टीप्लायर इफेक्ट' राजस्थान की अर्थव्यवस्था को व्यापक गति देगा और नए रोजगार सृजित करेगा।

भारत–अमेरिका ट्रेड डील और टैरिफ में ऐतिहासिक कटौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व, स्पष्ट दृष्टि और प्रभावी आर्थिक कूटनीति का परिणाम है। राजस्थान के लिए यह समझौता केवल व्यापारिक राहत नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ वैश्विक बाजार में आगे बढ़ने का अवसर है। यदि राज्य और केंद्र सरकार के प्रयासों के साथ उद्योग जगत इस अवसर का सही उपयोग करता है, तो राजस्थान आने वाले वर्षों में निर्यात के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सकता है और यही इस डील की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।

–अशोक परनामी,
पूर्व विधायक एवं
पूर्व मेयर जयपुर।

तारबंदी से सुरक्षा, बीमा से संबल : किसानों को करोड़ों रुपये का अनुदान मिला

विकसित भारत 2047 के सपने के केंद्र में अन्नदाता : सरकारी सहायता और योजनाओं ने खोले रास्ते, किसान ने दुनिया देखी

अमृता कटारा

भारतीय कृषि को अक्सर परंपरा के फ्रेम में बाँधकर देखा गया है–हल, बैल, मानसून और अनिश्चितता। लेकिन आज खेतों की ज़मीन के नीचे सिर्फ़ बीज नहीं, बदलाव भी दबाहुआ है। यह बदलाव न तो अचानक है और न ही पूरी तरह दृश्यमान होता है। यह धीरे–धीरे किसान की सोच, नीति और खेती में बदलाव और नियमित प्रयास से आता है। जिस कृषि को लंबे समय तक केवल जीविका का साधन माना गया, वह अब आत्मनिर्भरता और स्थायित्व की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही है। यह परिवर्तन इसलिए भी ज़रूरी हो गया है क्योंकि भारतीय कृषि आज दोहरी चुनौती से जूझ रही है। एक ओर बढ़ती आबादी की खाद्य आवश्यकताएँ हैं, दूसरी ओर छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका को सुरक्षित रखने की ज़िम्मेदारी। उत्पादन में बढ़ोतरी के बावजूद खेती जोखिम से मुक्त नहीं हुई है।

जलवायु परिवर्तन, बढ़ती लागत और बाज़ार की अस्थिरता ने किसान को लगातार अनिश्चितता में रखा है। ऐसे समय में कृषि का आधुनिकीकरण कोई वैचारिक बहस नहीं, बल्कि व्यवहारिक अनिवार्यता बन चुका है। 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना तब तक अधूरी रहेगी, जब तक खेतों में काम करने वाला किसान स्वयं को उस विकास का सहभागी न माने। इसी सोच के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में और राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कृषि को नीति के केंद्र में रखा है। किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, पीएम–कुसुम, अटल भू–जल योजना, किसान डिजिटल आईडी, तारबंदी और जैविक खेती जैसी योजनाएँ यह संकेत देती हैं कि सरकार ने खेती को अल्पकालिक राहत नहीं, बल्कि दीर्घकालिक योजना मानती है।

राज्य सरकार के अब तक के कार्यकाल में लगभग 59 हजार 039 सोलर पंपसेटों की स्थापना कर 900 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान दिया जाना यह बताता है कि सिंचाई और नवीनीकरण ऊर्जा के सवाल को स्थायी समाधान की ओर ले जाया जा रहा है। इसी तरह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लगभग 6,450 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम का वितरण यह दर्शाता है कि प्राकृतिक आपदाओं के समय किसान को आर्थिक सुरक्षा देने का प्रयास किया गया है। खेती में जोखिम कम हुए बिना नवाचार संभव नहीं होता। नीति का असर तब स्पष्ट दिखता है जब वह ज़मीन पर उतरती है।

राजस्थान में आयोजित ग्राम उत्थान शिविर इस मायने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहे है। योजनाओं की जानकारी, आवेदन की प्रक्रिया और समस्याओं का समाधान–सब कुछ एक ही मंच पर उपलब्ध होने से किसानों और प्रशासन के बीच की दूरी कम हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि जागरूकता केवल सूचना से नहीं, संवादसे आती है और यही इन शिविरों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रतापगढ़ जैसे जनजाति क्षेत्रों में यह बदलाव विशेष महत्व रखता है, जहाँ खेती लंबे समय तक केवल जीवन निर्वहन तक सीमित रही। छोटी जोतों और सीमित संसाधनों के बीच प्रतापगढ़ के जवाहरनगर के बाबूलाल मीणा द्वारा सरकार की सहायता से वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना यह बताती है कि जैविक खेती अब प्रयोग नहीं रही। कम लागत, बेहतर मूल्य और अतिरिक्त आय–ये परिणाम बताते हैं कि सही मार्गदर्शन मिलने पर किसान टिकाऊ विकल्पों की ओर बढ़ सकता है।

इसी ज़िले से किसान शंभूलाल पाटीदार का डेनमार्क एक्सपोज़र विज़िट पर जाना यह संकेत देता है कि कृषि प्रशिक्षण अब केवल तकनीक सिखाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सोच का दायरा भी बढ़ा रहा है। जब किसान दुनिया को देखने लगता है, तो अपनी ज़मीन को देखने का नज़रिया भी बदल जाता है। तारबंदी योजना ने भी खेती को स्थिरता दी है एवं किसानों के हितों कीरक्षा की है। जवाहरनगर की दुर्गा बाई मीणा और पिल्लू गाँव के पंकज कुमार मीना जैसे किसानों की कहानियाँ यह बताती हैं कि फसल सुरक्षा केवल नुकसान नहीं रोकती बल्कि कृषि को अधिक सुरक्षित बनती है।

राज्य में लगभग 34,395 किलोमीटर तारबंदी कर 377.66 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाना इस बात का संकेत है कि खेती को जोखिम से मुक्त करने की दिशा में ठोस प्रयास हुए हैं। इसके साथ ही 35,368 फार्म पॉन्ड के निर्माण पर 300 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान जल संरक्षण को खेती की बुनियाद बनाने की मंशा को दर्शाता है। इन सभी अनुभवों और आँकड़ों को साथ रखकर देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि प्रदेश के अन्नदाताओं का भविष्य जनहितैषी कार्यों की निरंतरता, ज़मीनी क्रियान्वयन और किसान की भागीदारी से आकार ले रहा है। खेत आज भी परंपरा से जुड़े हैं, लेकिन अब उनके साथ सुरक्षा, ज्ञान और उम्मीद भी खड़ी है–और शायद यही बदलाव की सबसे बड़ी पहचान है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा कृषि को नवाचार, सुरक्षा और सम्मान से जोड़ने की दिशा में जो व्यापक विजन सामने रखा, उसे राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ज़मीन पर आकार मिलता दिख रहा है। सोलर पंप से लेकर फसल बीमा, तारबंदी से लेकर जल संरक्षण तक–ये प्रयास यह संकेत देते हैं कि किसान को अब केवल उत्पादन की इकाई नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का सहभागी माना जा रहा है। जनजाति क्षेत्रों से सामने आई बदलाव की यह कहानियाँ यह भरोसा जगाती हैं कि जब नीति में निरंतरता हो और क्रियान्वयन में संवेदनशीलता, तो खेती केवल अतीत की विरासत नहीं रहती, वह भविष्य की बुनियाद बन जाती है।

शंभू लाल पाटीदार: वैश्विक अनुभव और सरकारी योजनाओं से बदली खेत की तस्वीर

प्रतापगढ़ जिले के प्रगतिशील किसान शंभू लाल पाटीदार ने पारंपरिक खेती को आधुनिक और लाभकारी कृषि में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है। उन्होंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी खेती को नई दिशा दी। सरकारी सहयोग से वे पॉलीहाउस में लाल और हरी शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें अधिक उत्पादन के साथ बेहतर बाजार मूल्य भी मिल रहा है। उनकी यह सफलता इस बात का उदाहरण है कि सही तरीके से लागू की गई सरकारी योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने के साथ–साथ टिकाऊ और नवाचारी कृषि को भी बढ़ावा देती है।

हाल ही में शंभू लाल पाटीदार को एक सरकारी कार्यक्रम के तहत डेनमार्क जाने का अवसर मिला, जहां उन्होंने उन्नत जैविक खेती की तकनीकों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया। उन्होंने इस अनुभव को अत्यंत लाभकारी बताते हुए कहा कि वहां उन्होंने उत्पादन बढ़ाने और खेती में वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने के कई महत्वपूर्ण गुर सीखे। सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल किसानों को वैश्विक ज्ञान, नई दक्षताएं और नवाचार करने का आत्मविश्वास प्रदान करती हैं।

–अमृता कटारा,
एपीआरओ, डीआईपीआर

बोर्ड परीक्षाओं के लिए कंट्रोल रूम शुरु

अजमेर, (निसं)। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 12 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के सफल, निष्पक्ष एवं सुचारु आयोजन को लेकर गुरुवार को कंट्रोल रूम की स्थापना की गई। इस अवसर पर बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने विधि–विधान के साथ मां सरस्वती की पूजा–अर्चना कर कंट्रोल बोर्ड का शुभारंभ किया।

बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि कंट्रोल रूम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य परीक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना तथा परीक्षा के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। कंट्रोल रूम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय में स्थापित किया गया है, जहां से पूरे प्रदेश की परीक्षा गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि कंट्रोल रूम के लिए चार अलग–अलग लैंडलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इन नंबरों के माध्यम से प्रदेश भर के परीक्षा केंद्र अधीक्षक एवं संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी परीक्षा के दौरान आने वाली किसी भी प्रकार की समस्या, अव्यवस्था या आपात स्थिति की जानकारी सीधे कंट्रोल बोर्ड को दे सकेंगे। प्राप्त सूचनाओं पर तुरंत कार्रवाई कर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बोर्ड प्रशासन का मानना है कि कंट्रोल बोर्ड की सक्रिय भूमिका से परीक्षा संचालन में पारदर्शिता बनी रहेगी और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या तकनीकी समस्या पर तुरंत नियंत्रण पाया जा सकेगा। इससे न केवल परीक्षा केंद्रों को मार्गदर्शन मिलेगा, बल्कि विद्यार्थियों को भी शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में परीक्षा देने का अवसर मिलेगा।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

शुक्रवार 6 फरवरी, 2026

फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, हस्त नक्षत्र रात्रि 12:2 तक, धृति योग रात्रि 11:37 तक, कौलव करण दिन 12:51 तक, चन्द्रमा आज कन्या राशि में संचार करेगा।

गृह स्थिति: सूर्य–मकर, चन्द्रमा–कन्या, मंगल–मकर, बुध–कुम्भ, गुरू–मिथुन, शुक्र–कुम्भ, शनि–मीन, राहु–कुम्भ, केतु–सिंह

आज कुमार योग सूर्योदय से रात्रि 12:24 तक है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:36 तक, लाभ–अमृत 8:36 से 11:19 तक, शुभ 12:41 से 2:03 तक, चर 4:46 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:14, सूर्यास्त 6:08

मेष
परिवार में चल रहे आपसी मतभेद दूर होंगे। अस्त–व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
घर–परिवार में सुख–शांति बनी रहेगी। परिवार में सुख–सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में धार्मिक–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

सिंह
आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बना रहेगा। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। चलते कार्यों में प्रगति होगी। परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।

कन्या
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल–आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

तुला
व्यावसायिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी। आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। मन में असंतोष बना रहेगा।

वृश्चिक
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

धनु
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। चलते कार्यों में प्रगति होगी। घर–परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है।

मीन
परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग–समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक–सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।